IASBABA 60 DAYS 2020: POLITY & CURRENT AFFAIRS-DAY 2

Q.1) मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये निगमों या कंपनियों के लिए भी उपलब्ध हैं।
2. ये निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।
3. ये पवित्र (sacrosanct) या स्थायी हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.1) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	**सत्य**	**असत्य**
उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं चाहे नागरिक, विदेशी या कानूनी व्यक्ति जैसे निगम या कंपनियां।	उनमें से अधिकांश राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध, कुछ अपवाद जैसे कि राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध और निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। जब राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार केवल निजी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन किए जाते हैं, तो कोई संवैधानिक उपचार नहीं होते हैं, केवल सामान्य कानूनी उपचार होते हैं।	वे पवित्र या स्थायी नहीं हैं। संसद उन्हें कम कर सकती है या निरस्त कर सकती है लेकिन केवल एक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तथा इसे एक साधारण अधिनियम द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह संविधान के 'बुनियादी ढांचे' को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है।

Q.2) निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' माना जाता है?

1. पंचायतें और नगर पालिकाएँ
2. ओएनजीसी
3. एनसीईआरटी
4. न्यायपालिका

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

a) 1 और 2
b) 1,2 और 3
c) 1,2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.2) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	**सत्य**	**असत्य**	**असत्य**
ऐसा कोई भी प्राधिकरण जिसके पास कोई भी कानून बनाने, किसी भी आदेश को पारित करने, विनियमन और उपनियम बनाने, आदि की शक्ति है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड और अन्य वैधानिक, संवैधानिक निकाय राज्य की परिभाषा में आते हैं।	वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय जो सरकार से वित्तीय संसाधन प्राप्त करते हैं, उन पर सरकार का समुचित नियंत्रण होता है तथा कार्यात्मक चरित्र जैसे कि ICAR, CSIR, ONGC, IDBI, विद्युत् बोर्ड, NAFED, दिल्ली परिवहन निगम आदि राज्य की परिभाषा में आते हैं।	वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय जो आमतौर पर सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं होते हैं, वे राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। उदाहरण स्वायत्त निकाय, सहकारिता, एनसीईआरटी आदि हैं।	न्यायपालिका राज्य नहीं है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने द नेशनल फेडरेशन ऑफ़ द ब्लाइंड, महाराष्ट्र और Anr v. के मामले में इस प्रश्न का उत्तर दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 'न्यायालय' की परिभाषा में प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय या प्रशासनिक क्षमता में निर्णय लेते समय, केवल "राज्य" शामिल हैं तथा न्यायिक पक्ष पर नहीं' ।

Q.3) भारतीय प्रणाली पर कानून के नियम (Rule of law) के निम्नलिखित में से कौन से अवयव लागू हैं?

1. मनमानी शक्ति का अभाव
2. कानून के समक्ष समानता
3. व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.3) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य

कानून के नियम की अवधारणा में निम्नलिखित तीन तत्व या पहलू हैं:
(i) मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति, अर्थात कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है।
(ii) कानून के समक्ष समानता, अर्थात सभी नागरिकों (अमीर या गरीब, उच्च या निम्न, आधिकारिक या गैर-आधिकारिक) की समान अधीनता जो सामान्य कानून न्यायालयों द्वारा प्रशासित भूमि के सामान्य कानून के लिए हो।
(iii) व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता, अर्थात् संविधान व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, जो कि कानून के न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किया जाता है बजाय कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है।

पहला और दूसरा तत्व भारतीय प्रणाली पर लागू होते हैं तथा तीसरा नहीं। भारतीय प्रणाली में, संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है।

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. उचित प्रतिबंध लगाने के लिए अपराध हेतु मानहानि और उकसाना एक आधार है।
2. अकेले कार्यकारी कार्रवाई द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता,	उचित प्रतिबंधों की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: (1) उनके तहत प्रतिबंध केवल या किसी कानून के अधिकार के तहत लगाया जा सकता है: कोई कार्यकारी

न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाने के आधार पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभ्यास पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।	प्रतिबंध अकेले बिना किसी कानून का पालन किए नहीं लगाया जा सकता है। (2) प्रत्येक प्रतिबंध उचित होना चाहिए। (3) प्रतिबंध 19 (2) से (6) में उल्लिखित उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए।

Q.5) विदेश यात्रा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है

a) अनुच्छेद 15
b) अनुच्छेद 19
c) अनुच्छेद 21
d) अनुच्छेद 22

Q.5) Solution (c)

अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
अनुच्छेद 19 देश के भीतर आवागमन अधिकार की रक्षा करता है।

Q.6) शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे 2002 के 86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
2. यह संविधान में सम्मिलित होने वाला मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी पहला ऐसा प्रावधान था।
3. यह अधिकार नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों, दोनों के लिए उपलब्ध है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.6) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 A) प्रावधान 2002 के 86 वें	इस संशोधन से पहले भी, संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों	यह नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों, दोनों के लिए भी

संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।	के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था।	उपलब्ध है।

Q.7) निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 13 के तहत 'कानून' (Law) माना जा सकता है?

1. अध्यादेशों
2. नागा प्रथागत कानून (Naga customary laws)
3. संवैधानिक संशोधन
4. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

a) 1 और 2
b) 1,2 और 3
c) 1,2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.7) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	सत्य
राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जैसे अस्थायी कानून को अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाता है।	कानून के गैर-विधायी स्रोत, अर्थात्, कानून की शक्ति वाले कस्टम या मान्यता को अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाता है।	अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि एक संविधान संशोधन कानून नहीं है और इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में कहा कि एक संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो संविधान के 'बुनियादी ढांचे' का एक हिस्सा है तथा इसलिए, इसे शून्य घोषित	अनुच्छेद 13 के तहत आदेश, उपनियम, नियम, विनियमन या अधिसूचना जैसे प्रत्यायोजित विधान (कार्यकारी कानून) की प्रकृति में वैधानिक उपकरण को कानून माना जाता है।

		किया जा सकता है।	

Q.8) भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसमें एक व्यक्ति को दूसरे के धर्म में परिवर्तन का अधिकार शामिल है।
2. इसके तहत, राज्य हिंदू धार्मिक संस्थानों के सुधार के लिए प्रावधान प्रदान कर सकता है।
3. इस अधिकार के तहत आने वाले हिंदुओं में सिख, पारसी, जैन और बौद्ध शामिल हैं

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.8) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
इसमें दूसरों में धार्मिक विश्वासों का प्रसारण और प्रसार या किसी के धर्म के सिद्धांतों को उजागर करना शामिल है। लेकिन, इसमें किसी अन्य व्यक्ति को एक व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन सभी व्यक्तियों को समान रूप से 'अंतश्चेतना की स्वतंत्रता' को प्रतिबंधित करता है।	राज्य को सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक वर्गों के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और समूहों के लिए सुधार प्रदान करने की अनुमति है।	इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं

Q.9) निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है / हैं?

1. समान काम के लिए समान वेतन
2. गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

4. पर्यावरण का संरक्षण और सुधार

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 3 और 4
c) केवल 4
d) 1,2 और 3

Q.9) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	**असत्य**	**सत्य**	**सत्य**
पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (d) एक समाजवादी सिद्धांत है।	समान न्याय को बढ़ावा देना तथा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 A) एक समाजवादी सिद्धांत है।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए (अनुच्छेद 46) एक गांधीवादी सिद्धांत है।	पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए (अनुच्छेद 48 A) एक उदार-बौद्धिक सिद्धांत है।

Q.10) निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित है?

1. 42 वां संशोधन अधिनियम: आय, पदस्थिति (status), सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना
2. 44 वां संशोधन अधिनियम: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना
3. 86 वां संशोधन अधिनियम: सभी बच्चों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल तथा शिक्षा, जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) 2 और 3

Q.10) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने नए निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा, जिससे राज्य को आय, पदस्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 38)।	उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने हेतु 1976 के 42 वें संशोधन अधिनियम ने निर्देशक सिद्धांत, (अनुच्छेद 43 A) जोड़ा।	2002 के 86 वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदल दिया, जिससे राज्य को सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

Q.11) निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए किया गया है?

1. बाल और किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम
2. मातृत्व लाभ अधिनियम
3. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन
4. आपराधिक प्रक्रिया संहिता

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1,2 और 3
c) 1,2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.11) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य
बाल और किशोर श्रम निषेध तथा विनियमन अधिनियम, (1986) को बच्चों और श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया	महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) और समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) बनाया गया है।	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हथकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, कॉयर बोर्ड, रेशम बोर्ड	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) ने राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया।

गया है।		आदि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए स्थापित किए गए हैं।	

Q.12) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत दिए गए निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं हैं?

1. देश की रक्षा करना
2. करों का भुगतान करना
3. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना
4. वोट देना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1,2 और 4
b) 2,3 और 4
c) 2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.12) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	**सत्य**	**असत्य**	**सत्य**
देश की रक्षा करना अनुच्छेद 51 A (d) के तहत एक मौलिक कर्तव्य है।	करों का भुगतान करने की विशेषता एक मौलिक कर्तव्य नहीं है।	सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 A (i) के तहत एक मौलिक कर्तव्य है।	वोट डालने की विशेषता कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है

Q.13) मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों की एक सूची है।
2. इनमें नैतिक कर्तव्यों के साथ-साथ नागरिक कर्तव्य दोनों शामिल हैं।
3. वे कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.13) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
जापानी संविधान, संभवतः, विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों की एक सूची शामिल है।	उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को बनाए रखना एक नैतिक संकल्पना है तथा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है।	वे कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसलिए, संसद उनमें से किसी को पूरा करने में विफलता के लिए उचित जुर्माना या सजा का प्रावधान कर सकती है।

Q.14) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं, क्योंकि उनके लिए राज्य को कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है।
2. निर्देशक सिद्धांतों को उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है तथा वे स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं।
3. मौलिक अधिकार सदैव निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभावी होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

a) 1 और 3
b) केवल 2
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.14) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	**सत्य**	**असत्य**
मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति हैं क्योंकि वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं।	निर्देशक सिद्धांतों को उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है तथा वे स्व-चालित रूप से लागू नहीं होते हैं।	मौलिक अधिकार आमतौर पर निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभावी होते हैं। इसके अपवाद हैं, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19

		द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 39 (b) और (c) में निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धांतों के अधीनस्थ के रूप में स्वीकार किया गया था।

Q.15) पुट्टस्वामी अधिनिर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार किसके अंतर्गत सुरक्षित है

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 19
3. अनुच्छेद 21

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.15) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और Anr. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो मानता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत निजता के अधिकार को एक मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है।

Q.16) निम्नलिखित में से किस कानून को अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अमान्य होने से बचाया गया है?

1. निगमों का समामेलन (Amalgamation of corporations)
2. निगमों के शेयरधारकों के अधिकारों में संशोधन
3. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण
4. राज्य द्वारा संपत्तियों का प्रबंधन संभालना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1, 2 और 4

b) 1, 3 और 4
c) 2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.16) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	सत्य

अनुच्छेद 31A कानून की पाँच श्रेणियों को चुनौती देता है तथा अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 19 (भाषण, सभा, आवागमन आदि के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देता है । वे कृषि भूमि सुधार, उद्योग और वाणिज्य से संबंधित हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
(a) राज्य द्वारा संपत्ति और संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण;
(b) राज्य द्वारा संपत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण;
(c) निगमों का समामेलन;
(d) निगमों के निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारों का शमन या संशोधन; तथा
(e) खनन पट्टों की निकासी या संशोधन।

जब राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (अनुच्छेद 30) की संपत्ति का अधिग्रहण करता है, तो उसे मुआवजा प्रदान करना होगा।

Q.17) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अनुच्छेद 35 राज्य सूची में निर्दिष्ट मामलों पर एक कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता को विस्तृत करता है।
2. अनुच्छेद 35 राज्य विधायिका को कुछ मामलों पर कानून बनाने के लिए प्रतिबंधित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
अनुच्छेद 35, उपरोक्त निर्दिष्ट मामलों पर एक कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता का विस्तार करता है, भले ही उन मामलों में से कुछ राज्य विधानसभाओं (यानी, राज्य सूची) के दायरे में आ सकते हैं।	अनुच्छेद 35 कहता है कि कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित होगी तथा राज्य विधानसभाओं में नहीं।

Q.18) अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान प्रदान करता है, जब मार्शल लॉ भारतीय क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में लागू हो। मार्शल लॉ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. 'मार्शल लॉ' की व्याख्या को संविधान में 'एक क्षेत्र में सेना के शासन' के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. मार्शल लॉ की घोषणा के परिणाम स्वरुप बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का निलंबन हो जाता है।
3. यह सरकार और सामान्य कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) केवल 3
d) उपरोक्त सभी

Q.18) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
'मार्शल लॉ' शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। शाब्दिक रूप में, इसका अर्थ 'सैन्य शासन' है।	सुप्रीम कोर्ट ने बरक़रार रखा है कि मार्शल लॉ की घोषणा के कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है।	यह सरकार और सामान्य कानून न्यायालयों को निलंबित करता है।

Q.19) उत्प्रेषण (certiorari) रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है

1. न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण
2. प्रशासनिक अधिकारी
3. वैधानिक निकायों (Legislative bodies)

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.19) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य

पहले, उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती थी, न कि प्रशासनिक प्राधिकारण के विरुद्ध। हालांकि, 1991 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है।	उत्प्रेषण विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है।

Q.20) अनुच्छेद 28 चार प्रकार के शिक्षण संस्थानों के बीच अंतर करता है। धार्मिक निर्देश निम्नलिखित में से किसमें पूरी तरह से निषिद्ध है?

1. राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थान
2. राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएँ
3. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान
4. राज्य द्वारा प्रशासित संस्थान लेकिन किसी धर्मस्व (endowment) या ट्रस्ट के तहत स्थापित।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 1,2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.20) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	असत्य	असत्य	असत्य

इस प्रकार, अनुच्छेद 28 चार प्रकार के शैक्षिक संस्थानों के बीच अंतर करता है:
(a) राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित किए गए।
(b) राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी धर्मस्थ (endowment) या ट्रस्ट के तहत स्थापित।
(c) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।
(d) राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएँ।
(a) में धार्मिक निर्देश पूरी तरह से प्रतिबंधित है जबकि (b) में, धार्मिक निर्देश की अनुमति है। (c) और (d) में, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक निर्देश की अनुमति है।

Q.21) भारतीय ऑर्किड की पहली व्यापक जनगणना में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) के अनुसार निम्नलिखित तथ्य हैं

1. संपूर्ण आर्किड परिवार को CITES (वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन) के परिशिष्ट II के तहत सूचीबद्ध किया गया है
2. भारत के 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में से, हिमालयी क्षेत्र आर्किड प्रजातियों के मामले में सबसे समृद्ध है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.21) Solution (c)

भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) ने भारतीय ऑर्किड की पहली व्यापक जनगणना प्रस्तुत की है, जिसमें ऑर्किड प्रजाति या taxa की कुल संख्या 1,256 है।

ऑर्किड को मोटे तौर पर तीन जीवन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है: एपिफाइट (अक्सर लिथोफाइट कहे जाने वाले तथा पथरीली चट्टान पर उगने वाले पौधों सहित अन्य पौधों पर उगने वाले पौधे, स्थलीय (भूमि और पर्वतीय चोटियों पर उगने वाले पौधे) तथा माइकोहेट्रोट्रॉफिक (पौधे जो माइकोरोज़िया कवक से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जो एक संवहनी पौधे की जड़ों से जुड़ी होती है)।

देश में पाए जाने वाले सभी ऑर्किड में से लगभग 60%, जो कि 757 प्रजातियां हैं, एपिफाइट हैं, 447 स्थलीय हैं और 43 माइकोहेट्रोट्रॉफ़िक हैं।

आर्किड प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश से 612 प्रजातियों के साथ दर्ज की जाती है, उसके बाद सिक्किम 560 प्रजातियां तथा पश्चिम बंगाल; दार्जिलिंग हिमालय में 479 प्रजातियों के साथ उच्च प्रजाति की सघनता भी है।

कथन विश्लेषण:

कथन 1	कथन 2
सत्य	**सत्य**
संपूर्ण आर्किड परिवार को CITES के परिशिष्ट II के तहत सूचीबद्ध किया गया है तथा इसलिए वनीय ऑर्किड के किसी भी व्यापार पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध लगाया गया है।	भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्र आर्किड प्रजातियों के मामले में सबसे समृद्ध है, इसके बाद पूर्वोत्तर, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।

Source - https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/india-is-home-to-1256-species-of-orchid-says-first-comprehensive-survey/article28429797.ece

Q.22) भारत में ओवर द काउंटर (Over the Counter- OTC) दवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ओटीसी दवाओं की नीति केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा बनाई गई है
2. दर्द निवारक, खांसी उपचार और एंटी-एलर्जी को ओटीसी दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.22) Solution (b)

रोगों को ठीक करने के लिए स्वयं केमिस्ट से दवा के रूप में लोगों द्वारा ली जाने वाली दवाओं को ओवर द काउंटर (OTC) दवाएं कहा जाता है।

10 शहरों में 20,000 लोगों के बीच लाइब्रेट (Lybrate) द्वारा किए गए 2015 के सर्वेक्षण से पता चला है कि 52% लोगों ने स्व-दवा (self-medication) का अभ्यास किया।
सरकार एक ओटीसी दवा नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो दवाओं पर अधिक स्पष्टता ला सकती है ताकि एक व्यापक आबादी तक पहुंच हो सके।
बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की संस्था ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ फ़ार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ़ इंडिया (ओपीपीआई) ने पिछले एक वर्ष में सरकार के साथ मिलकर ओटीसी नीति के मसौदे को इनपुट प्रदान किया है।

कथन विश्लेषण:

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
भारत में ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित विनियमन का अभाव है जो रोगी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।	अधिकांश ओटीसी दवाओं को आमतौर पर दर्द निवारक, कफ उपचार, एंटी-एलर्जी, जुलाब, विटामिन, एंटासिड आदि में वर्गीकृत किया जाता है।

Source - https://www.thehindu.com/news/national/other-states/wide-access-to-otc-drugs-frees-up-govt-resources/article28693476.ece

Q.23) कुरील द्वीप समूह किसके मध्य स्थित हैं

a) ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर
b) जापान सागर और प्रशांत महासागर
c) ओखोटस्क सागर और बेरिंग सागर
d) आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर

Q.23) Solution (a)

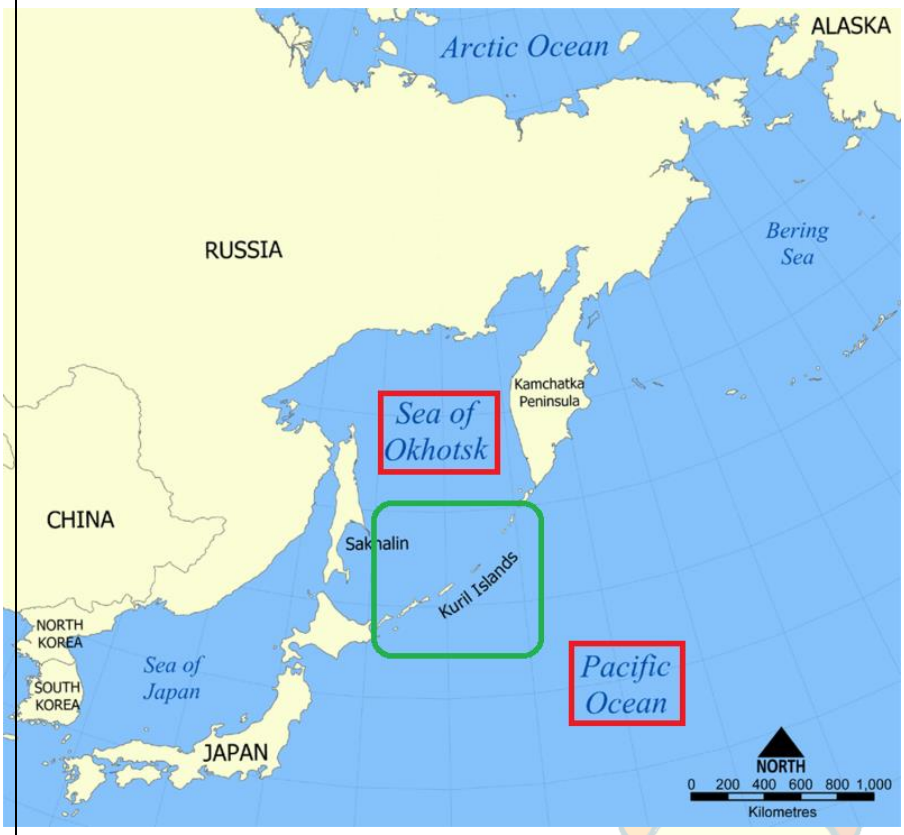

कुरील द्वीप या कुराइल द्वीप रूस के सखालिन ओब्लास्ट (Sakhalin Oblast) में एक ज्वालामुखीय द्वीपसमूह है, जो उत्तर-पूर्व में जापान के होक्काइडो से रूस के कामचटका तक लगभग 1,300 किलोमीटर (810 मील) दूर तक फैला हुआ है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर से ओखोटस्क सागर को अलग करता है।

इसमें 56 द्वीप और कई छोटी चट्टानें हैं। इसमें वृहद् कुरील श्रृंखला और लघु कुरील श्रृंखला शामिल हैं।

सभी द्वीप रूसी प्रशासन के अधीन हैं। जापान चार सबसे दक्षिणी द्वीपों का दावा करता है, जिसमें दो सबसे बड़े (इटुरुप और कुनाशीर) शामिल हैं, अपने क्षेत्र के साथ-साथ शिकोतन और हबोमई द्वीप समूह के हिस्से के रूप में, जिसके कारण कुरील द्वीप विवाद चल रहा है।

विवादित द्वीपों को जापान में देश के "उत्तरी क्षेत्र" के रूप में जाना जाता है।

2018 में, जापान के साथ द्वीपों के पुन: एकीकरण पर रुसो-जापानी वार्ता फिर से शुरू हुई।

Source - https://www.thehindu.com/news/international/japan-calls-russian-pms-visit-to-disputed-island-regrettable/article28793643.ece

Q.24) 'ASRAAM' मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

a) यह तीव्र गति की हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल है।
b) इसे "दागो और भूल जाओ" (fire-and-forget) मिसाइल के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

c) ASRAAM का लक्ष्य बहुत छोटी सीमा तक लक्ष्य के पता लगाना और उसके विरुद्ध लॉन्च करना है
d) इसमें गति उच्च तथा परास 50 किमी तक है।

Q.24) Solution (c)

यह एडवांस्ड शार्ट रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (ASRAAM) है।
यह एक उच्च गति, अत्यंत युद्धाभ्यास, ऊष्मा मांग वाली, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
MBDA द्वारा निर्मित, इसे "दागो और भूल जाओ" मिसाइल के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
ASRAAM का लक्ष्य बहुत लंबी सीमा तक लक्ष्य के पता लगाना और उसके विरुद्ध लॉन्च करना है, जहां तक AMRAAM के जो शुरुआती संस्करण हैं, शत्रु द्वारा अपने हथियारों से गोली चलाने से पहले ही वह पता लगाकर मार सकने में सक्षम है।
इस संबंध में ASRAAM अन्य IR मिसाइलों की तुलना में AMRAAM के साथ समानता साझा करता है,
आवश्यक शक्ति प्रदान करने के लिए, ASRAAM को 16.51 सेमी (61/2) इंच) व्यास के रॉकेट मोटर पर बनाया गया है। यह ASRAAM को काफी अधिक गति (thrust) प्रदान करता है तथा इसलिए गति और 50 किमी तक सीमा बढ़ जाती है।
ASRAAM व्यापक रूप से 25 किमी से अधिक की रेंज के भीतर एक विजुअल रेंज (WVR) एयर डोमिनेन्स मिसाइल के रूप में उपयोग किया जाता है।

Source - https://www.thehindu.com/news/national/iaf-to-adopt-asraam-missile-across-its-fighter-fleet/article28359593.ece

Q.25) निम्नलिखित का मिलान करें

1. 'दस्तक अभियान'- A) घातक तीव्र इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) और जापानी एन्सेफलाइटिस (JE) रोग को समाप्त करने के लिए।
2. 'उत्कर्ष 2022 '- B) मैक्रो आर्थिक विकास के लिए आरबीआई के जनादेश के प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
3. 'ऑपरेशन मिलाप'- C) तस्करी या अपहृत व्यक्ति को बचाने के लिए तथा अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए।
4. 'ऑपरेशन संकल्प' - D) भारतीय नौसेना का फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में ऑपरेशन

नीचे दिये गये कथनों में से कौन सही है?

a) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
b) 1-A, 2-D, 3-B, 4-C
c) 1-B, 2-C, 3-D, 4-A
d) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D

Q.25) Solution (a)

Statement Analysis:

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य
इंसेफेलाइटिस और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) के सहयोग से 'दस्तक' अभियान चलाया गया। अभियान स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्वच्छता अभियान शुरू करेगा। जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) एक मच्छर जनित फ्लेविवायरस (flavivirus) है। यह डेंगू, पीत ज्वर और वेस्ट नाइल वायरस के समान जीन के अंतर्गत आता है।	'उत्कर्ष 2022' भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्यम-अवधि की रणनीति का ढांचा है, जो विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक विकास के अनुरूप है। यह अगले तीन वर्षों के लिए रोडमैप है।	'ऑपरेशन मिलाप', दिल्ली पुलिस की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) सूचना विकसित करती है, तस्करी करने वाले या अपहरण किए गए व्यक्ति को बचाती है और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करती है।	भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में हाल की समुद्री घटनाओं के बाद, भारतीय जहाजों की सुरक्षा और रक्षा का आश्वासन देने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में 'ऑपरेशन संकल्प' आरंभ किया है। ओमान की खाड़ी में बढ़ते तनाव के मद्देनजर ऑपरेशन शुरू किया गया है, जहां हाल ही में दो तेल टैंकरों पर हमला किया गया था। अमेरिका ईरान को हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है, इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है।

Q.26) 'मॉडल कर सूचना विनिमय समझौतों (TIEA)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एक मॉडल TIEA को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा विकसित किया गया था।
2. यह एक बाध्यकारी समझौता नहीं है।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.26) Solution (c)
Statement Analysis:

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
कर सूचना विनिमय समझौते (TIEA) एक विशेष आपराधिक या नागरिक कर जांच या नागरिक कर मामलों से संबंधित अनुरोध पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं। सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान पर ओईसीडी ग्लोबल फोरम वर्किंग ग्रुप द्वारा एक मॉडल TIEA विकसित किया गया था।	यह समझौता, जो अप्रैल 2002 में जारी किया गया था, एक बाध्यकारी उपकरण नहीं है, लेकिन इसमें द्विपक्षीय समझौतों के लिए दो मॉडल शामिल हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

इस समझौते का उद्देश्य सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह OECD ग्लोबल फोरम वर्किंग ग्रुप द्वारा सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान पर विकसित किया गया था।

OECD द्वारा हानिकारक कर प्रथाओं को संबोधित करने के लिए समझौता हुआ। सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान की कमी हानिकारक कर प्रथाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। समझौता हानिकारक कर प्रथाओं पर ओईसीडी की पहल के प्रयोजनों के लिए सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के मानक का प्रतिनिधित्व करता है।

जून 2015 में, राजकोषीय मामलों की OECD समिति (CFA) ने समझौते के लिए एक मॉडल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी। मॉडल प्रोटोकॉल का उपयोग प्राधिकारों द्वारा किया जा सकता है, यदि वे अपने मौजूदा TIEAs के दायरे का विस्तार करना चाहते हैं, तो सूचना के स्वचालित और / या सहज विनिमय को भी कवर कर सकते हैं।

ऐसा करने में, क्षेत्राधिकार तब एक सामान्य सक्षम मानक के अनुसार सूचना के स्वत: आदान-प्रदान या एक TIEA पर देश-दर-देश रिपोर्ट के स्वत: आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकारी समझौते को आधार बनाने में सक्षम होते हैं, ऐसे मामलों में विशेष रूप से जहां यह (अभी तक) एक प्रासंगिक बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी समझौते के तहत सूचना का आदान-प्रदान संभव नहीं है।

यदि वे एक नए TIEA में सूचना प्रावधानों के स्वत: और सहज आदान-प्रदान को शामिल करना चाहते हैं, तो क्षेत्राधिकार मॉडल प्रोटोकॉल के अनुच्छेदों के शब्दों का उपयोग करने का चयन भी कर सकते हैं।

Q.27) 'वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (Financial Benchmark Administrators- FBA)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. FBA को भारत में हर समय दस करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल संपत्ति के साथ निगमित होना चाहिए।
2. RBI द्वारा विनियमित वित्तीय साधनों के लिए FBAs बाजारों में 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' को नियंत्रित करता है।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.27) Solution (b)
Statement Analysis:

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
FBA के लिए पात्रता मानदंड: • FBA भारत में निगमित कंपनी होगी। • FBA हर समय एक करोड़ रूपए की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति बनाए रखेगा।	FBA निर्माण, संचालन और प्रशासन के नियमों, जैसे कीमतों, दरों, सूचकांकों, मूल्यों या वित्तीय साधनों से संबंधित संयोजन को नियंत्रित करता है, जो समय-समय पर गणना और वित्तीय साधनों या किसी अन्य वित्तीय अनुबंध के मूल्य निर्धारण या मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं।

Read More -
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11601&Mode=0

Q.28) 'प्यूर्टो विलियम्स' (Puerto Williams), जो हाल ही में समाचारों में था, कहाँ स्थित है?

a) चिली
b) प्यूर्टो रिको

c) अर्जेंटीना
d) न्यूजीलैंड

Q.28) Solution (a)

यह चिली में नवारिनो द्वीप पर स्थित नगर, बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। इसके सामने बीगल चैनल है। प्यूर्टो विलियम्स ने विश्व के सबसे दक्षिणी नगर होने का दावा किया है।

Q.29) 'गामा पोर्टल' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।
2. यह एक पोर्टल है जहां भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.29) Solution (c)
Statement Analysis:

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भ्रामक विज्ञापनों (GAMA) के खिलाफ शिकायतों के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है।	यह एक पोर्टल है जहां भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। टेलीविज़न, रेडियो, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र, बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, दीवार-लेखन आदि के माध्यम से कोई विज्ञापन या प्रचार, प्रकृति, विशेषताओं, गुणों या भौगोलिक वस्तुओं, सेवाओं या वाणिज्यिक गतिविधियों की गलत व्याख्या करने के लिए ताकि गलत जानकारी दी जा सके,ऐसे कार्यों को मोटे तौर पर उपभोक्ता के लिए भ्रामक विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

Q.30) 'E-2020 पहल' (E-2020 initiative) निम्नलिखित में से किस बीमारी / विकार से संबंधित है?

a) गैर - संचारी रोग
b) मलेरिया
c) एचआईवी / एड्स
d) कोरोनावायरस

Q.30) Solution (a)

मई 2015 में, विश्व स्वास्थ्य सभा ने मलेरिया 2016-2030 के लिए एक नई वैश्विक तकनीकी रणनीति का समर्थन किया, इस 15 वर्ष की अवधि में वैश्विक मलेरिया के बोझ को कम करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें लक्ष्य की प्रगति को ट्रैक करने का प्रावधान भी था। 2020 के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य कम से कम 10 देशों में मलेरिया का उन्मूलन है, जहाँ 2015 में बीमारी थी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, देशों को 2020 में शून्य स्वदेशी मामलों की रिपोर्ट करनी चाहिए।

Read More - https://www.who.int/malaria/media/e-2020-initiative-qa/en/

Copyright © by IASbaba
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of IASbaba.